www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 73 | जौनपुर, गुरूवार, 29 अक्टूबर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम सक्रिय

कोलकाता, एजेंसी। मौसम विशेषज्ञ बंगाल की खाड़ी में बन रही स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, जिससे एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह सिस्टम मजबूत होकर उत्तरी तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है। अगर यह चक्रवात का रूप ले लेता है, तो इसके चेन्नई और आंध्र प्रदेश के बीच तट से टकराने की संभावना है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि चक्रवात बनेगा ही या यह किस जगह तट से टकराएगा। लेकिन यह पूर्वानुमान ऐसे समय में आया है, जब चक्रवात 'अर्नब' तमिलनाडु से होकर गुजरा है, जो अब आंध्र प्रदेश और उसके आगे उत्तर की ओर बढ़ गया है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. वीआर दुरई ने बताया कि मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मॉडल इसके उत्तरी तमिलनाडु की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सिस्टम का अंतिम रास्ता अभी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "जब तक यह सिस्टम चक्रवात में नहीं बदल जाता, तब तक यह बताना मुश्किल है कि यह किस दिशा में जाएगा और कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि, मौजूदा मौसम पूर्वानुमान मॉडल बताते हैं कि यह उत्तरी तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है। राज्य के अलग–अलग हिस्सों में बारिश कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मजबूत होने के बाद यह सिस्टम किस तरफ बढ़ता है।

छत्तीसगढ़ में चक्रवात 'अर्नब' का असर, भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

छत्तीसगढ़, एजेंसी। चक्रवाती तूफान अर्नब कल बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को पार कर चुका है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अलग–अलग स्थानों पर हल्की से लेकर अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को बस्तर, बलरामपुर– रामानुज गंज, सूरजपुर, कोरिया और कोरबा जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच भी उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तथा गरज–चमक के साथ वज्रपात की संभावना बनी रहेगी। किसानों को सलाह दी है कि धान, मक्का और तिलहन जैसी खरीफ फसलों की जो फसलें पक चुकी हैं, उनकी जल्द कटाई कर सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करें। जिन किसानों ने कटाई शुरू कर दी है, उन्हें कटी हुई उपज को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर रखने को कहा गया है। खेतों में जल भराव रोकने के लिए निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल गेहूं, चना और मसूर जैसी रबी फसलों की बुआई स्थगित रखें।

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से प्रयास जारी - सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख आर्थिक विकास केंद्र बनाने और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी में सिंगापुर के उद्योगपतियों और निवेशकों के 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, शहरी नियोजन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई। फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल का यह उत्तर प्रदेश दौरा निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश भी पिछले साढ़े नौ वर्षों में अपनी पिछड़ी आर्थिक छवि से बाहर निकलकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक बजट और प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना वृद्धि हुई है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी तीन गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिना जनता पर कोई नया कर लगाए उत्तर प्रदेश लगातार राजस्व अधिशेष वाला राज्य बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2026 में सिंगापुर यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से हुई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए बताया कि उस दौरान लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षा, स्थिरता और तेजी से काम पूरा करने का भरोसा दे रही है। अब सरकार का लक्ष्य निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर उत्पादन शुरू कराना है। समझौता ज्ञापन से लेकर विनिर्माण और परियोजना की शुरुआत से उत्पादन तक हर चरण में निवेशकों को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने शेयर किया गीता का श्लोक, कहा– 'जैसी श्रद्धा, वैसा ही होती है मनुष्य की सोच और आचरण'

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार सुबह एक संस्कृत सुभाषितम् को शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि मनुष्य की सोच, उसका विश्वास और उसका आचरण उसकी श्रद्धा के ही परिणाम होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः" यह श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 17 (श्रद्धात्रयविभागयोग), श्लोक 3 से लिया गया है। इस श्लोक का अभिप्राय है कि 'हे भारत। प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य की सोच, उसका विश्वास और उसका आचरण उसकी श्रद्धा के ही परिणाम होते हैं। वह जैसी श्रद्धा रखता है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है।' यह श्लोक महाभारत के उस अध्याय के संदर्भ में है, जब अर्जुन के यह पूछने पर कि जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर केवल अपनी श्रद्धा से पूजा–आर्चना करते हैं, उनकी निष्ठा सात्त्विकी, राजसी या तामसी, किस प्रकार की होती है, भगवान श्रीकृष्ण इसका उत्तर देते हैं। हमारी श्रद्धा की प्रकृति ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है श्रीकृष्ण समझाते हैं कि हमारी श्रद्धा की प्रकृति ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है और हमारी श्रद्धा का गुण हमारे मन की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्रीकृष्ण श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। सुभाषितम् में सभी के कल्ल्याण और समृद्धि के लिए प्रकृति की रक्षा और देखभाल के महत्व पर बल इसके पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने 'संस्कृत सुभाषितम्' में सभी के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रकृति की रक्षा और देखभाल के महत्व पर बल दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात `अर्नब' के मद्देनजर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की

नई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्री ने इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को आपदा के समय लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपदा के प्रभाव का आंकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता तय करने के लिए जल्द ही अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें भेजी जाएंगी। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस आपदा के समय लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि NDRF और SDRF की टीमें सक्रियता के साथ युद्धस्तर पर बचाव व राहत कार्य कर रही हैं। आपदा के प्रभाव का आंकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता तय करने के लिए जल्द ही अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आपदा से प्रभावित लोगों की कठिनाइयां कम करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के साथ खड़ी है।

पर्यटन परियोजनाएं नवंबर तक पूरी कर दिसंबर में लोकार्पण के लिए तैयार करें - जयवीर सिंह

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 की स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं को नवंबर तक पूरा कर दिसंबर में लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के आकलन और अन्य प्रक्रियाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।पर्यटन मंत्री ने बुधवार को पर्यटन भवन में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को राज्य योजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के आकलन तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्ययोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारियों और संबंधित प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान कराने को कहा।

बैठक में एक अप्रैल से 26 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल पर आवंटित संपत्तियों से पट्टा किराये की वसूली का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गोरखपुर के रामगढ़ ताल, देवरिया और सीतापुर के नैमिषारण्य सहित कई स्थानों की संपत्तियों पर पट्टा किराये का बकाया नहीं है। कालिंजर, राधाकुंड, सुमेर सिंह किला, देवा शरीफ, शिकोहाबाद, गोपीगंज, मुंशीगंज और कपिलवस्तु की संपत्तियों के संबंध में भी बकाया नहीं होने की जानकारी दी गई। विंध्याचल, भदोही झील महल रेस्टोरेंट, मऊ तथा आगरा और मथुरा की संपत्तियों से पट्टा किराया वसूले जाने की भी जानकारी दी गई। मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025–26 तक जिला महोत्सवों के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष आयोजित कार्यक्रमों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समीक्षा की। उन्होंने दीपोत्सव–2026 की तैयारियों और आयोजन संबंधी कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि आयोजन को भव्य और यादगार बनाने में कोई कमी न रहे। वाराणसी में देव दीपावली–2026 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।बैठक में संग्रहालयों के क्यूरेशन कार्य, मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना और मंत्रिपरिषद के विचारार्थ लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। जयवीर सिंह ने निर्देश दिया कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर वेबसाइट पर क्यूआर कोड जोड़ने का काम तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने प्राचीन, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर लगाए जाने वाले शिलालेखों में संबंधित स्थल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मान्यताओं और लोककथाओं को शामिल करने पर जोर दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराई आसियान की केंद्रीय भूमिका

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक–प्लस को संबोधित करते हुए भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो–पैसिफिक विजन' के मूल आधार के रूप में आसियान की केंद्रीय भूमिका के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि यह मंच एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध इंडो–पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक से सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ने, नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और रक्षा सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, "इस अवसर पर भारत आसियान की केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो –पैसिफिक विजन का आधार है।" उन्होंने फिलीपींस द्वारा बैठक के सफल आयोजन और गर्मजोशी भरे स्वागत–सत्कार के लिए आभार व्यक्त किया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य एशिया– प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। इससे अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों की पड़ोसी देशों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

नीति में बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, व्यापार, कौशल विकास, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए भारत –आसियान सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत 'सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति' यानी महासागर की अवधारणा पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू की गई इंडो–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव भारत के समुद्री विजन को स्पष्ट दिशा देती है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा सचिव गिल्बर्टो सी. थियोडोरो जूनियर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के रास्ते तलाशे। समुद्री सुरक्षा तथा संयुक्त रक्षा उत्पादन पर विशेष चर्चा हुई। भारत का यह रुख आसियान के साथ गहरे जुड़ाव और खुले, मुक्त तथा समावेशी इंडो –पैसिफिक की दिशा में उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

चक्रवात `अर्नब' के मद्देनजर ओडिशा को सहायता के आश्वासन पर सीएम माझी ने अमित शाह का आभार जताया

ओडिशा, एजेंसी। मुख्यमंत्री माझी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर ओडिशा को हरसंभव सहायता का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार। भारत सरकार का यह सहयोग और समर्थन, हर ओडिया (ओडिशावासी) की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगा।" मुख्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें ओडिशा में अर्नब चक्रवात के प्रभाव, प्रभावित जिलों की मौजूदा स्थिति और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। भारत सरकार का यह सहयोग और समर्थन लोगों की जान बचाने, प्रभावित परिवारों की मदद करने और पूरे राज्य में राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगा।" इससे पहले अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया था, "चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस आपदा के समय लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हरसंभव मदद दी जाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम में जुट गई हैं और युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य चला रही हैं। आपदा के असर का आकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता तय करने के लिए जल्द ही आईएमसीटी भेजी जाएंगी।

अखिलेश यादव ने शिक्षक–स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत पर दी बधाई

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड चुनाव में पार्टी के विजयी प्रत्याशियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई दी। उन्होंने जीत के बाद कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई हो–हल्ला या जुलूस नहीं निकाला जाए, ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर सके और समाजवादी पार्टी पर हुड़दंग करने के आरोप न लगाए जा सकें। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से सतर्क रहना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी सभी विजयी प्रत्याशियों का अभिनंदन करेगी। संभव हुआ तो वह स्वयं उनके क्षेत्रों में पहुंचकर सम्मान करेंगे। उन्होंने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों से उन कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों की सूची तैयार करने को कहा, जिन्होंने चुनाव में उनका सहयोग किया है। ऐसे सभी लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बेईमानी और धांधली का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को हराने के लिए कथित तौर पर कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। गोरखपुर शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को मतगणना में गड़बड़ी करके हराने की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक कारणों के साथ 'हाता नहीं भाता' भी एक प्रमुख वजह है।अखिलेश यादव ने कहा कि डॉ. संजयन त्रिपाठी के साथ हुए कथित उत्पीड़न को उनका समाज देख रहा है। गोरखपुर शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी और आगरा शिक्षक क्षेत्र के प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ हुए घटनाक्रम को शिक्षक समुदाय नहीं भूलेगा।

दीपों की आभा से जगमगाएगी रामनगरी, भव्य दीपोत्सव की तैयारियों पर मंथन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले विधायक वेद प्रकाश गुप्ता

विभागों में बेहतर समन्वय बनाकर समय से तैयारियां पूरी करने पर हुई चर्चा

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।इस दौरान उन्होंने दीपोत्सव के आयोजन की तैयारियों और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि दीपोत्सव को भव्य, दिव्य और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर लगातार नजर रखी जा रही है,ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।गौरतलब है कि मंगलवार को आईजी प्रवीण कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया था। अधिकारियों ने संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए थे।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दीपोत्सव अयोध्या की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर तैयारियों को निर्धारित समय में पूरा कराया जाएगा,जिससे दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आयोजन की गरिमा और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

संपादकीय

इससे हासिल होगा

श्रम सर्वे अगर गिग कर्मियों और घरेलू काम में लगी महिलाओं की केवल गिनती करता है, जबकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का कानूनी ढांचा तैयार नहीं होता, तो इस डेटा संग्रह का लाभ संदिग्ध ही रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार की समझ बदलने की औपचारिक पहल कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जनवरी 2027 से अपने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में यह बदलाव लागू करेगा। इसके तहत गिग और प्लेटफॉर्म को कर्मियों तथा घरेलू काम में अवैतनिक योगदान करने वाली महिलाओं को रोजगारशुदा गिना जाएगा। इस परिवर्तन के पक्ष में तर्क है कि जोमैटो, स्विगी, ओला, अर्बन कंपनी आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग काम कर रहे हैं। नए सर्वे से उनकी संख्या मालूम होगी। पता चलेगा कि वे कितने घंटे काम करते हैं। इसी तरह कारोबार में महिलाओं के योगदान को भी मान्यता मिलेगी। इसका एक और परिणाम होगा कि पीएलएफएस के आंकड़ों में श्रम बल में मौजूद लोगों और रोजगारशुदा लोगों की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी। शविकास का कथानकच्य लिखने के लिहाज से ये आंकड़े काम के साबित होंगे! लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या उन आंकड़ों से संबंधित कर्मियों के हालात बदलेंगे? गिग वर्कर्स को प्लैटफॉर्म कंपनियां श्कर्मचारीच्य नहीं, बल्कि श्स्वतंत्र ठेकदारच्य मानती हैं। इसलिए उन्हें ना न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलती है, ना स्वास्थ्य बीमा, और ना ही पेंशन। सरकार के सोशल सिक्योरिटी कोडके तहत अपेक्षित सुविधाएं शायद ही कहीं धरातल पर अमल में आई हैं। ऐसे में सर्वे अगर केवल उनकी गिनती करता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का कानूनी ढांचा तैयार नहीं होता, तो इस डेटा संग्रह का लाभ संदिग्ध ही रहेगा। महिलाएं रोज अपने कई घंटे बच्चों–बुजुर्गों की देखभाल, और घरेलू कार्यों में बिना किसी वित्तीय मुआवजे के लगाती हैं। बहरहाल, नए सर्वे में उनके अवैतनिक श्रम को दर्ज करने का प्रतीकात्मक महत्त्व चाहे जो हो, उससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने की कोई संभावना नहीं बनेगी। जब तक बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल का मजबूत सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे क्रेच और केयर सेंटर्स) तैयार नहीं होता, अवैतनिक कार्य का बोझ महिलाओं के कंधों से नहीं हट पाएगा। इसलिए असल चुनौती आंकड़े इकऋा करने की नहीं, बल्कि श्रम कानूनों में गिग कर्मियों के अनुकूल संशोधन और महिलाओं को आर्थिक संबल देने की योजनाओं को लागू करने की है। इस मामले में सरकार चुप है!

यूरोप में यूपी के 'योगी मॉडल' पर अमल के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ

कमलेश

यूरोप में कानून–व्यवस्था, हिंसक प्रदर्शनों, संगठित अपराध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन–शैली पर

चर्चा एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत विषय है। लेकिन इसका विश्लेषण करते समय एक बुनियादी सवाल समझना आवश्यक है कि क्या यूरोप को यूपी के श्योगी मॉडलश की सख्ती अपनाने की जरूरत है, या उसे उस मॉडल के कुछ चुनिंदा प्रशासनिक उपायों से सीख लेनी चाहिए? यहां पर यह बुनियादी सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2017 के बाद अमेरिका–यूरोप ने योगी मॉडल की आलोचना की थी! लिहाजा, इस प्रश्न का उत्तर यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, मानवाधिकार संबंधी प्रतिबद्धताओं और उत्तर प्रदेश में अपनाई गई नीतियों के वास्तविक परिणामों को साथ रखकर ही दिया जा सकता है। लेकिन जब इस्लामिक अतिवादी स्थानीय असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर यूरोप का इस्लामीकरण पर उतारू हों और ईरान का परोक्ष बरदहस्त उन्हें प्राप्त हो तो अमेरिका के बाद यूरोपीय विवशता समझी जा सकती है। सबसे पहला सवाल यह है की 'योगी मॉडल' से हमारा आपका क्या आशय है? तो माकूल जवाब यही होगा कि राजनीतिक विमर्श में 'योगी मॉडल' का प्रयोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था को प्राथमिकता देने, अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई, संगठित अपराध पर नियंत्रण, प्रशासनिक सख्ती और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसी नीतियों के लिए किया जाता है। हालाँकि, इन सभी उपायों को एक ही श्रेणी में रखना उचित नहीं है। अपराध की जाँच, दोषसिद्धि, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा अलग–अलग कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। चूंकि यूपी में बेलगाम अल्पसंख्यक अपराधियों, सत्ता संरक्षित बाहुबलियों, इनसे जुड़े मनबढ़ युवाओं और शातिर अपराधियों के इशारे पर अपराध कर रहे बहुसंख्यक अपराधियों को नियंत्रित करने में यूपी के योगी मॉडल ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, इसलिए चारो तरफ से जल रहे फ्रांस, इटली जैसे यूरोपीय देशों के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। सर्वप्रथम इटली की प्रमुख और मोदी की मित्र जॉर्जिया मेलोनी ने यूपी के योगी मॉडल पर अमल करने की घोषणा की, तत्पश्चात मोदी के दूसरे मित्र फ्रांस के प्रमुख मैक्रो ने जब यूपी के योगी मॉडल की अच्छी नीतियों पर अमल करना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार श्गैंगश सक्रिय हो गया और यूरोपीय देशों को उस नकारा लोकतंत्र की दुहाई देने लगा, जहां के बेलगाम लोग श्जुल्मी पूंजीवादी अड्डोंश को फूंकने के बजाय अपने देश के सार्वजनिक जगहों, नागरिक सुविधाओं और ठिकानों को ही फूंक रहे हैं! तीन, राज्य की विश्वसनीयतारू नागरिकों को यह भरोसा दिलाना कि शांतिपूर्ण जीवन, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी मॉडल का प्रभाव उसके नाम या राजनीतिक लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसके परिणामों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन से मापा जाना चाहिए। एक, कानून–व्यवस्था की बहस में बदलावरू यदि यूरोपीय देश उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गति, पुलिस–प्रशासन के समन्वय और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, तो उनकी आंतरिक सुरक्षा नीतियों में बदलाव आ सकता है। इससे भारत के प्रशासनिक अनुभवों में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ सकती है। दो, भारत की सॉफ्ट पावर और नीतिगत प्रतिष्ठारू भारत के किसी राज्य की प्रशासनिक नीति पर यूरोप में गंभीर चर्चा होना भारतीय संघीय व्यवस्था के अनुभवों को आंतरिक सुरक्षा नीतियों में बदलाव आ सकता है। इससे भारत के प्रशासनिक अनुभवों में अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ सकती है। यूरोप में पुलिस कार्रवाई के साथ नागरिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और न्यायिक समीक्षा का विशेष महत्त्व है। यूरोप की परिषद ने 23 अक्टूबर 2026 के आसपास जारी अपने हालिया वक्तव्य में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और हिंसा करने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करने तथा पुलिस बल के कानूनी और आनुपातिक इस्तेमाल पर जोर दिया है। यदि यूरोपीय सरकारें भारतीय राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण, डिजिटल निगरानी के कानूनी ढाँचे या प्रशासनिक समन्वय जैसे क्षेत्रों में उपयोगी अनुभव पाती हैं, तो तकनीकी सहयोग और नीतिगत संवाद के अवसर बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ बताते हैं कि इसे अभी एक संभावित दिशा समझना चाहिए, न कि यूरोप द्वारा योगी मॉडल स्वीकार कर लेने का प्रमाण! तीसरा अहम सवाल है कि क्या यूरोप में 'बुलडोजर नीति' भी अपनाई जा सकती है? तो जवाब होगा कि यहीं पर इस बहस का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर 'बुलडोजर मॉडल' राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा रहा है। लेकिन अवैध निर्माण हटाना और किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उसकी संपत्ति गिराना, दोनों अलग बातें हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट किया कि केवल किसी आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, किसी की संपत्ति गिराना असंवैधानिक है। न्यायालय ने नोटिस, सुनवाई और न्यायिक समीक्षा से जुड़े निर्देश भी दिए। लिहाजा, यूरोप में भी ऐसी किसी नीति को लागू करने के लिए स्थानीय कानून, संपत्ति अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई और आनुपातिक कार्रवाई के मानकों का पालन आवश्यक होगा। इसलिए यूरोप के लिए संभावित सीख यह नहीं कि वह बिना कानूनी प्रक्रिया के कठोर दंडात्मक कार्रवाई अपनाए, बल्कि यह कि अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई प्रभावी, प्रमाण–आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन हो। चौथा महत्वपूर्ण सवाल है कि योगी मॉडल बनाम यूरोपीय व्यवस्था की तुलनात्मक दृष्टि क्या है? इसे हमलोग विषय दर विषय, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश के मॉडल से जुड़ी बहस और यूरोपीय व्यवस्था की प्रमुख कसौटी के आधार पर निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं यूरोप की परिषद के मानवाधिकार मानकों में पुलिस कार्रवाई के लिए आवश्यकता, आनुपातिकता और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। ये मानक हिंसक घटनाओं से निपटने के साथ–साथ शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की रक्षा भी करते हैं। जहां तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसके संभावित प्रभाव की बात है तो इससे भारत की प्रशासनिक छवि मजबूत होगी। यदि उत्तर प्रदेश की किसी नीति से अपराध नियंत्रण या पुलिस–प्रशासन के समन्वय में मापने योग्य सुधार सिद्ध होता है, तो भारत अपने अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय नीति–चर्चाओं में प्रस्तुत कर सकता है। इससे भारतीय राज्यों के प्रशासनिक प्रयोगों पर शोध और संवाद को बढ़ावा मिल सकता है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र है, इसलिए भारत की बातों को अनसुनी करना अन्य देशों के लिए घातक भी हो सकता है।

विदा हो रहे हैं पांच प्रदेशों के मौजूदा नरेश

पंकज शर्मा

आंकड़ों का अंकगणित कुछ भी हो, बीजगणित खुल कर संकेत दे रहा है कि इन सभी प्रदेशों की मौजूदा हुकूमतों के लिए अगले चुनावों में अपनी वापसी दर्ज कराना मुश्किघ्ल है। ज् 2022 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के मद्देनजर अंकों के पीछे छिपे उस बीजमंत्र को समझिए, जिस की वजह से पांचों प्रदेशों में 2027 की शुरुआत वहां के वर्तमान शासकों के लिए मुसीबतों की गठरी और विपक्ष के लिए सौगातों का संदूक ले कर आ रही है। अगले साल फरवरी–मार्च में पांच राज्यों दृ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर दृ में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन में से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बाकघी चारों में भारतीय जनता पार्टी की। आंकड़ों का अंकगणित कुछ भी हो, बीजगणित खुल कर संकेत दे रहा है कि इन सभी प्रदेशों की मौजूदा हुकघ्मतों के लिए अगले चुनावों में अपनी वापसी दर्ज कराना मुश्किघ्ल है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें दोबारा नहीं बनेंगी। उत्तर प्रदेश में उसे सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं होगा। पंजाब में श्आप्च्य की सरकार का लौटना भी मुमकिन नहीं लगता है। 2022 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के मद्देनजर अंकों के पीछे छिपे उस बीजमंत्र को समझिए, जिस की वजह से पांचों प्रदेशों में 2027 की शुरुआत वहां के वर्तमान शासकों के लिए मुसीबतों की गठरी और विपक्ष के लिए सौगातों का संदूक ले कर आ रही है। सब से पहले उत्तर प्रदेश। वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 403 में से 255 सीटें जीती थी। मगर इस जीत के गलीचे के नीचे छिपे इस अपशिष्ट पर जरा नजर डालिए कि जीती गई सीटों में से 23 पर भाजपा पांच हजार से कम वोट से, 3 सीटें वह तीन हजार से कम वोट के अंतर से, 11 सीटें दो हजार से कम वोट से, 11 ही सीटें एक हजार से कम वोट से और 7 सीटें पांच सौ से भी कम वोट के अंतर से जीती थी। यानी 55 सीटें ऐसी हैं, जो अगले चुनाव में ढाई सौ से ढाई हजार वोट इधर–उधर होते ही भाजपा की झोली से नीचे गिर सकती हैं। स्पष्ट बहुमत 202 सीटों का है। 255 में से 55 खिसक गईं तो योगी आदित्यनाथ को सरकार बनाने लायकघ बहुमत अकेले भाजपा के भरोसे तो मिलेगा नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार पहले से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। इसे समझने के लिए इन तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पिछले चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थीं। 38 और सीटें ऐसी थीं, जो वह बहुत कम वोट के अंतर से हारी थी। 13 सीटों पर उस की हार का फकर्घ पांच हजार वोट से कम था, 14 पर वह तीन हजार से भी कम वोट से, 7 पर एक हजार से कम वोट से और 4 पर पांच सौ से भी कम वोट के फकर्घ से हारी थी। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस ने अलग–अलग लड़ा था। सपा ने 347 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 32 प्रतिशत की सफलता–दर हासिल की थी। सपा–गठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा विधानसभा के 184 क्षेत्रों में आगे रही है। कांग्रेस विधानसभा के 39 क्षेत्रों में पहले क्रम पर रही। यानी दोनों मिल कर 223 सीटों पर भाजपा से आगे रहे हैं। भाजपा के अभी 255 विधायक हैं, मगर लोकसभा के चुनाव में उन में से सिफ 162 की सीटों पर भाजपा को बढ़त मिल पाई है। अगर एनडीए के बाकघी दलों को भी शामिल कर लें तो भी यह आंकड़ा 174 पर पहुंचता है। यानी 93 सीटों का नुकघ्सान तो भाजपा को सीधे–सीधे हो रहा है और एनडीए को मिला कर भी योगी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए 28 विधायकों की जरूरत और होगी। युवाओं के देशव्यापी आंदोलन के चलते भाजपा की हालत दिनोंदिन और खराब ही हो रही है। सो, मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश से इस बार भाजपा की विदाई हो रही है। अब आइए उत्तराखंड पर। वहां भाजपा 70 में से 47 सीटें जीती थी। इन में से 8 सीटें उसे पांच हजार से कम वोट के अंतर सें, 4 सीटें तीन हजार वोट से कम से और 2 सीटें पर एक हजार वोट से कम के अंतर से मिली थीं। यानी 14 सीटें ऐसी हैं, जो इस बार उस के हाथ से खिसक सकती हैं। स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 36 है। भाजपा उस से 3 अंक पीछे रह सकती है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 19 सीटें मिली थीं। मगर 22 विधानसभा क्षेत्रों में उस की हार का अंतर पांच हजार वोट से कम रहा था। 7 सीटें वह तीन हजार वोट से कम के अंतर से हारी थी और 2 सीटों पर तो उस की हार का फकर्घ एक हजार से भी कम वोट का था। अगर इन सभी सीटों पर इस बार कांग्रेस अपनी मजबूती बरकरार रख पाती है तो उसे 41 सीटों पर जीत मिल सकती है। जाहिर है कि उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ स्थानीय क्षोभ के चलते वहां से भी भाजपा की विदाई के बहुत ठोस आसार नजर आ रहे हैं। पंजाब में भाजपा की जमीनी मौजूदगी न पिछले विधानसभा चुनाव में थी और न इस बार दिखाई दे रही है।

ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग ने मिलकर दिया करारा जवाब

नीरज

चुनाव आयोग पर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवालों की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार हमला करना और तथ्यों के सामने आने के बाद भी राजनीतिक आरोपों की धार बनाए रखना लोकतांत्रिक विमर्श की स्वस्थ परंपरा नहीं हो सकती। हम आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे के जरिए उन आरोपों का जवाब दिया है, जिनके माध्यम से आयोग की निर्णय प्रक्रिया और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग का पक्ष सामने आने के बाद अब इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक आरोपों के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। दस्तावेज क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है और अदालत के सामने कौन–सी दलीलें रखी गई हैं, यह देखना भी उतना ही जरूरी है। हम आपको यह भी बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह को 10 दिन का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद करने का फैसला किया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने अभी न तो आयोग के पक्ष को अंतिम रूप से स्वीकार किया है और न ही याचिकाकर्ताओं के आरोपों को सही ठहराया है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले को आगे बढ़ाएगी। दूसरी ओर, आयोग के हलफनामे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर से जुड़े तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से ही इन निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। हलफनामे को भी ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। किसी फाइल पर किसी अधिकारी या निर्वाचन आयुक्त की टिप्पणी, सवाल अथवा सुझाव दर्ज होने का अर्थ अपने आप यह नहीं होता कि आयोग ने अंतिम निर्णय भी उसी टिप्पणी के आधार पर लिया। आयोग ने अपने हलफनामे में इसी अंतर को स्पष्ट किया है। उसका कहना है कि फाइलें निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक निर्वाचन आयुक्त से दूसरे निर्वाचन आयुक्त और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती हैं। जरूरी मामलों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी भी ली जा सकती है, जिसे बाद में रिकॉर्ड पर दर्ज किया जाता है। आयोग का तर्क है कि आंतरिक विचार–विमर्श को अंतिम निर्णय के साथ मिलाकर देखना उचित नहीं है। यह दलील उन आरोपों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिनमें दावा किया गया था कि एसआईआर से जुड़े 14 निर्णय दोनों निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद आयोग के नाम पर लिए गए। लेकिन आयोग ने इन आरोपों के आधार को चुनौती देते हुए कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट अपने आप में आरोपों का निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं हो सकती। अब याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करना है और अदालत को यह तय करना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड से क्या निष्कर्ष निकलता है। दूसरा बड़ा मुद्दा फॉर्म–6 को लेकर है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। आयोग ने कहा है कि वैधानिक फॉर्म–6 में संशोधन नहीं किया गया। उसके मुताबिक, एसआईआर के दौरान मांगा गया अतिरिक्त घोषणा–पत्र अलग दस्तावेज है, जिसे मूल आवेदन–पत्र में संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि आयोग ने यह स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की प्रस्तुति से फॉर्म–6 में बदलाव होने का आभास पैदा हो सकता था। इसके बाद 21 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉर्म–6 और अलग एसआईआर घोषणा–पत्र में विभाजित करने की व्यवस्था किए जाने की बात भी कही गई। यही वह बिंदु है जहां आयोग के पक्ष को संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। किसी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उसमें सुधार करना प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। यदि ऑनलाइन व्यवस्था से भ्रम पैदा हुआ था, तो उसे अलग करना उपयोगी कदम हो सकता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष अपने आप नहीं निकलता कि हर विवाद समाप्त हो गया। असली कसौटी यह है कि व्यवस्था कानून के अनुरूप है या नहीं और पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की

परेशानी तो नहीं हो रही। साथ ही आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी अपना पक्ष रखा है। उसका कहना है कि जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पुरानी मतदाता सूचियों से नहीं मिल पाता, उनके घर जाकर बूथ स्तर के अधिकारी दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को सामान्यतः सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी और असाधारण मामलों में सुनवाई की जा सकती है। आयोग ने यह भी कहा है कि मृत्यु, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करने के लिए आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों को शामिल करने वाली समिति का उल्लेख किया गया है। इन दलीलों से आयोग यह बताना चाहता है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों की पहचान करना आवश्यक है, लेकिन किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटना भी उतना ही गंभीर विषय है। अब बात ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व की। किसी मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यक्षमता का फैसला इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि विपक्ष उनके कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या निर्णय कानून के अनुरूप लिए जा रहे हैं, क्या उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है ।

जनता अब खुद सवाल तय कर रही है

श्रुति व्यास

सवाल है कोई पार्टी यदि सत्ता में बैठकर भी विपक्ष की तरह लड़ती रहे और विपक्ष में पहुँचकर भी कोई पार्टी खुद को सत्ताधारी समझती रहे तो लोकतंत्र का क्या होगा? पिछले बारह वर्षों की भारतीय राजनीति का यह अजीब किस्सा है। भाजपा सरकार चलाते हुए भी कांग्रेस से ऐसे लड़ती रही मानो देश अभी उसी के कब्जे में हो। कांग्रेस विपक्ष में बैठी रही, लेकिन इस भाव से उबर नहीं पाई कि सत्ता तो उसी की है, बस किसी ने छीन ली है। एक उस सरकार से लड़ती रही जो जा चुकी थी। दूसरी यह मानने को तैयार नहीं हुई कि उसकी सरकार जा चुकी है। सो बार–बार चुनाव हुए। पूरी ताकत से हुए। टेलीविजन पर घमासान लगातार रहा। आरोप लगे, जवाब आए। लेकिन देश की राजनीतिक बहस कितनी आगे बढ़ी? सरकार के पास अपनी कमियों के लिए कांग्रेस थी। कांग्रेस के पास अपनी दुर्दशा के लिए भाजपा। दोनों को एक–दूसरे की जरूरत थी। दोनों इस इंतजाम में सहज भी हो गए। मैं हाल में कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में बार–बार यही बात सोचती हुई थी। दिल्ली से दूर थी। उसके रोज के राजनीतिक शोर से भी। सोचा था, कुछ दिन उससे छुट्टी मिलेगी। लेकिन वहाँ लोगों की बातचीत में राजनीति को लेकर ऐसी उत्सुकता मिली जो दिल्ली में लंबे समय से महसूस नहीं हुई थी। लोग सवाल पूछ रहे थे। केवल नाराजगी में नहीं। जानने की इच्छा से। इस संभावना के उत्साह में कि आगे कुछ बदल भी सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का क्या होगा? सीजेपी में कितना दम है? उसका आंदोलन क्या सचमुच सत्ता प्रतिष्ठान को परेशान कर सकता है? जेन जी का विरोध कुछ दिनों का उबाल है या नौजवानों के भीतर कुछ ज्यादा गहरा पक रहा है? और इन सबके बीच घूमता वह सवालकृक्या भाजपा वाकई उतनी अजेय है जितनी दिखाई देती है? सवालों से अधिक मुझे उन्हें पूछने की सहजता ने चौंकाया। ऐसा नहीं कि सब भाजपा के खिलाफ थे। या सबकी उम्मीद कांग्रेस से थी। किसी को शक था, किसी को उम्मीद। कुछ को शायद इसी संभावना में मजा आ रहा था कि राजनीति का अगला पन्ना अभी लिखा नहीं गया है। वर्षों से दिल्ली कश्मीर की चर्चा करती आई है। कश्मीर एक समस्या है। उसे समझना है, संभालना है, उसका समाधान करना है। और अब कश्मीर में बैठी मैं सुन रही थी कि लोग दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ क्या चल रहा है? आगे क्या होगा? किसकी कितनी ताकत है? मानो इस बार पहेली दिल्ली हो गई हो। इसे भारतीयों का राजनीतिक गपशप का पुराना शौक मान सकते हैं। लेकिन क्या बात इतनी ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम राजनीति के तयशुदा नतीजों के इतने आदी हो गए हैं कि अनिश्चितता की थोड़ी–सी गुंजाइश भी उत्साह पैदा करने लगी है? जब रोज बताया जाए कि कौन जीतेगा, कौन हार चुका है और किसका कोई भविष्य नहीं है, तब इस धारणा में छोटी–सी दरार भी देखने लायक हो जाती है। एलन मस्क के हवाले से एक सवाल चला कि क्या भारत के असली बॉस मुकेश अंबानी हैं? न कोई प्रमाण, न इससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसे सवाल का चल पड़ना और उसमें लोगों की दिलचस्पी भी कुछ बताती है। लोग पैसे और सत्ता के रिश्ते पर बात करना चाहते हैं। किसकी कहाँ तक पहुँच है? सरकार के फैसलों में किसका कितना असर है? सार्वजनिक सत्ता और निजी संपत्ति के बीच की दूरी आखिर बची कितनी है? फिर सोनिया गांधी की आने वाली आत्मकथा श्बिलॉन्गिंगरू ए जर्नी ऑफ लक्च्य की चर्चा है। सोचें, एक व्यक्ति का जीवन कितने वर्षों तक भाजपा की राजनीति की सामग्री बना रहा। इटली में जन्मी महिला। भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार में विवाह। फिर कांग्रेस की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करना। बावजूद इसके पार्टी और सरकार में प्रभाव बनाए रखना। उनके विदेशी मूल पर कितने चुनाव लड़े गए, कितने भाषण हुए! मेरी उत्सुकता केवल यह नहीं है कि वे क्या बताएँगी। यह भी है कि देश फिर उसी पुरानी बहस में लौटेगा या उनके जीवन को कुछ अलग ढंग से पढ़ पाएगा? कांग्रेस अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई। भाजपा ने भी उसे बाहर निकलने देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। गांधी परिवार कांग्रेस के लिए विरासत रहा तो भाजपा के लिए निशाना। दोनों के लिए अतीत काम का रहा। उधर फारूक अब्दुल्ला हैं। उन्होंने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे दिल्ली में नाराजगी का परिचित दौर शुरू हो जाए। बारामूला में पाकिस्तान पर उनकी टिप्पणी आई और अपेक्षित प्रतिक्रियाएँ भी आ गईं। मैं सोच रही थी, क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौरान अपेक्षाकृत शांति से पुराने योद्धा ऊबने लगे हैं? या दिल्ली को याद दिलाना चाहते हैं कि वे अभी हैं। केवल सम्मानित बुजुर्ग बनकर बैठ जाने का उनका इरादा नहीं है। लेकिन यहाँ भी फर्क देखिए। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को चर्चा में वापस ला रहे थे। और जिन कश्मीरियों से मेरी बात हो रही थी, वे भारत की अंदरूनी राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें दिल्ली की सत्ता के भीतर और उसके सामने बनती चुनौतियाँ जाननी थीं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल की आने वाली आत्मकथा श्विदाउट फियर ऑर फेवरच्य की चर्चा है। न्यायिक मतभेदों की यादें। संस्थाओं के भीतर काम करने के अनुभव। सत्ता और अधिकार के उन गलियारों का विवरण जिन्हें बाहर बैठा नागरिक पूरी तरह देख नहीं पाता। न्यायाधीशों से कहा जाता है कि उनके फैसले बोलने चाहिए। वे अपने संस्मरणों में बोलें तो लोग यह भी जानना चाहेंगे कि फैसलों के पीछे का अनुभव क्या था। ऊपर से देखें तो इन बातों का आपस में संबंध नहीं है। एक अरबपति की कथित टिप्पणी। एक राजनीतिक परिवार की कहानी। एक पुराने नेता का विवाद। एक पूर्व न्यायाधीश की यादें। लेकिन मुझे इनमें एक बात साझा लगी। इन्हें चर्चा का विषय बनने के लिए भाजपा और कांग्रेस की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। लोगों की अपनी उत्सुकता है। वे जानना चाहते हैं कि जो बताया जा रहा है, उसके पीछे क्या है? ताकत वास्तव में कहाँ है? और जो आज स्थायी दिखाई देता है, वह कितना स्थायी है? शायद राजनीति के जरूरत से ज्यादा अनुमान योग्य हो जाने पर ऐसा होता है। लोग उसमें कुछ अनसोचा तलाशने लगते हैं। कोई संभावना, जिस पर अभी पार्टियों की मुहर न लगी हो। भाजपा की पिछले वर्षों की बड़ी ताकत यही रही कि देश किस बात पर बहस करेगा, यह वह तय करती थी। कांग्रेस विरोध भी करती थी तो प्रायरू उसी के चुने विषयों पर। इतिहास हो, राष्ट्रवाद हो, गांधी परिवार हो या असहमत व्यक्ति की देशभक्तिकृसवाल भाजपा बनाती थी। कांग्रेस उत्तर देने में जुट जाती थी। वह सफाई देती थी, प्रतिवाद करती थी और अगले सवाल का इंतजार करती थी। चुनावी लिहाज से भाजपा को इसका खूब लाभ मिला। लेकिन क्या आज भी लोगों की राजनीतिक जिज्ञासा उसी घेरे में बँधी हुई है? क्या वे अब भी वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें वर्षों से सुनाया जा रहा है? इससे कांग्रेस अपने आप प्रासंगिक नहीं हो जाती। उसकी अपनी परीक्षा है। मतदाता सूचियों और चुनाव आयोग पर आरोपों को लेकर एक नवंबर को रामलीला मैदान में उसकी प्रस्तावित रैली को ही लें। यही वह मैदान है जहाँ कभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा जमा हुआ था।

महामहिम थिएरी माथू, भारत में फ्रांस के राजदूत, ने सुनील भारती मित्तल को शेवेलिए द ल ऑर्द्र नेशनल द ला लेजियों दनर से सम्मानित किया

आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री थिएरी माथू ने भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री सुनील भारती मित्तल को 28 अक्टूबर को फ्रांस निवास में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान शेवेलिए द लश्ऑर्द्र नेशनल द ला लेजियों दनर (नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के शूरवीर) का प्रतीक चिह्न प्रदान किया। फ्रांस ने सुनील भारती मित्तल को उनके भारत–फ्रांस आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रति सतत समर्पण के साथ–साथ दूरसंचार, डिजिटल अवसंरचना और उपग्रह संचार के क्षेत्र में उनकी अग्रणी उपलब्धियों के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लेजियों दनर, से सम्मानित किया है। सभा को संबोधित करते हुए, राजदूत थिएरी माथू ने भारत–फ्रांस संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में श्री भारती के अथक योगदान को रेखांकित करते हुए कहारू श्री सुनील भारती मित्तल को शेवेलिए द लश्ऑर्द्र नेशनल द ला लेजियों दनर प्रदान किया जाना भारत–फ्रांस आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता है। श्री मित्तल ने न केवल फ्रांस के बहुराष्ट्रीय बीमा समूह एक्सा तथा दूरसंचार उपकरण निर्माता अल्काटेल–लुसेंट के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से फ्रांसीसी व्यापार के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया है, बल्कि फ्रांसीसी उपग्रह दिग्गज यूटेलसैट में अपने निवेश के माध्यम से रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की फ्रांस की महत्वाकांक्षा का भी समर्थन किया है। यह सम्मान व्यापार संबंधों को गहरा करने तथा नींव आधारित साझेदारी, उच्च–स्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं और उपग्रह संचार क्षेत्र में भारी निवेश के माध्यम से फ्रांस के साथ रणनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करने के प्रति श्री मित्तल की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए फ्रांस की कृतज्ञता तथा प्रशंसा को दर्शाता है।ष पुरस्कार स्वीकार करते हुए, श्री सुनील भारती मित्तल ने कहा, ष्फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से मिले इस सौम्य पुरस्कार से मैं अभिभूत और विनम्र हूं। फ्रांस के साथ मेरा जुड़ाव 1992 में एयरटेल की स्थापना के समय शुरू हुआ था, जब कॉम्पैनी जेनराल देजो ने भारत में मोबाइल टेलीफोनी शुरू करने के लिए भारती के साथ हाथ मिलाया था, और आज यह यूरोपीय उपग्रह चौंपियन यूटेलसैट के उपाध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका के माध्यम से जारी है। मैं राष्ट्रपति मैक्रों के प्रति आभार के साथ इस सम्मान को स्वीकार करता हूं तथा भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की नवीकृत प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। जैसे–जैसे दोनों देश भारत–फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के तहत अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी में अपने सहयोग को गहरा करना जारी रखे हुए हैं, यूरोपीय उपग्रह चौंपियन यूटेलसैट के उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुनील भारती मित्तल, भारत–फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं।

प्रेम और निष्काम भक्तिसे ही परमात्मा की प्राप्ति संभव - पं. रजनीकांत द्विवेदी

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नगर के विवाह मैरेज लॉन में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन बुधवार को कथाव्यास पं. रजनीकांत द्विवेदी ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, गोवर्धन पूजा, गोपियों के अनन्य प्रेम और माता–पिता के वात्सल्य का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रेम, समर्पण और निष्काम भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गोवर्धन पूजा के प्रसंग की व्याख्या करते हुए कथाव्यास ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति के महत्व और उसके संरक्षण का संदेश दिया। प्रकृति मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ऐसे में उसका संरक्षण करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण और गोपियों के प्रेम

का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि गोपियों की भक्ति निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनके प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। गोपी भाव को समझने के लिए बाहरी दृष्टि के बजाय अंतरूकरण से चिंतन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का नाम राधा है। मनुष्य जिस प्रवृत्ति और विचारधारा के प्रभाव में रहता है, उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। मन की चंचलता पर नियंत्रण रखकर उसे परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। पं. द्विवेदी ने माता–पिता के प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा कि पिता अपने पुत्र को सफल देखना चाहता है और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। वहीं मां का वात्सल्य ममता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ और लाभ–हानि की अपेक्षा नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति भी अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर प्रेम एवं समर्पण के मार्ग पर चलने से होती है।

उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रेम, सदाचार, प्रकृति संरक्षण और निष्काम भक्ति को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कथा की मुख्य यजमान विमला सेठ हैं। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह, सेवा भारती के विभागाध्यक्ष डॉ. तेज सिंह, डॉ. बीएस उपाध्याय, गंगाधर शुक्ल, चंद्रप्रकाश सोनी, ओमजी सहाय, नीरज शाह, पूनम तिवारी, निर्मला राय, गीता शुक्ला, विवेक सेठ, विनीत सेठ, अर्चना सेठ, विशाल सेठ, विपिन सेठ, उज्ज्वल सेठ, ओम सेठ, वंशिका सेठ, चंद कुमार सेठ, राजाराम त्रिपाठी, हर्षित सेठ और हार्दिक सेठ सहित गठना कोठी परिवार के सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पेट परीक्षा के चलते जौनपुर में 30 अक्टूबर को स्कूल–कॉलेज बंद

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)–2026 के आयोजन के मद्देनजर जौनपुर में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को स्कूल–कॉलेजों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में गुरुवार शाम जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर कुमार ने आदेश जारी कर संबंधित शिक्षण संस्थानों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, च्ज्–2026 परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को दो पालियों में आयोजित की जा रही है। 30 अक्टूबर को सामान्य शिक्षण दिवस होने के कारण परीक्षा के सुचारु संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए शासन के निर्देश पर शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित संबंधित शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संबंधित संस्थानों को शामिल किया गया है। हालांकि, परीक्षा के लिए ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक और कर्मचारी अवकाश के दिन भी अपने निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। डीआईओएस और बीएसए ने सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

कैंसर संस्थान में अब पांच दिन में मिलेगी बायोप्सी की जांच रिपोर्ट

लखनऊ, (संवाददाता)। चक गंजरिया स्थित कैंसर संस्थान में 2.16 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल पैथोलॉजी लैब स्थापित की गई है। इस सुविधा से कैंसर मरीजों की बायोप्सी जांच रिपोर्ट अब पांच दिन में मिल सकेगी। अभी रिपोर्ट आने में आठ से 10 दिन लगते थे। मंगलवार को संस्थान में ऑन्कोपैथोलॉजी विभाग के स्थापना दिवस समारोह में निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने लैब का शुभारंभ किया। निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने कहा कि समय पर जांच रिपोर्ट मिलने से मरीजों का इलाज जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी। कैंसर के उपचार में एक–एक दिन महत्वपूर्ण होता है।

मैक्स अस्पताल, लखनऊ के डॉक्टरों ने ट्रॉमा केयर में गोल्डन आवर की अहमियत बताई, चेहरे की जटिल सर्जरी के मामलों की जानकारी दी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद समय पर इलाज मिलने से जान बचाने और लंबे समय तक रहने वाली दिव्यांगता का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है। इसी बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ ने विश्व ट्रॉमा दिवस के बाद एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इसमें चोट लगने के बाद के शुरुआती महत्वपूर्ण समय यानी गोल्डन आवर की अहमियत बताई गई। इस दौरान तेजी से जांच, सही समय पर चोट की पहचान और अलग–अलग विशेषज्ञों के तालमेल से किया गया इलाज जानलेवा जटिलताओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस सत्र में न्यूरोसर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। डॉ. मनु रस्तोगी, सीनियर डायरेक्टर, न्यूरोसर्जरीय डॉ. सतिंदर पाल सिंह तुलसी, डायरेक्टर, डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरीय डॉ. दिव्यांशु दत्त द्विवेदी, एसोसिएट डायरेक्टर, ऑर्थोपेडिक्स और डॉ. सौरभ कुमार सिंह, कंसल्टेंट एवं इंचार्ज, इमरजेंसी मेडिसिन ने गंभीर चोटों की पहचान, एंबुलेंस की त्वरित उपलब्धता और समय पर इमरजेंसी इलाज शुरू करने के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि गंभीर चोटों के मामलों में अलग–अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

अस्पताल ने चेहरे की गंभीर चोटों से जुड़े 2 जटिल मामलों की जानकारी भी साझा की। इनमें 12 वर्षीय सार्थक पांडेय का मामला शामिल है, जिन्हें साइकिल दुर्घटना में चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। उनके निचले जबड़े की 3 अलग–अलग जगहों पर हड्डी टूट गई थी, जिससे चेहरे की बनावट भी प्रभावित हुई थी। उन्हें मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ लाया गया। यहां डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर, डॉ. सतिंदर पाल सिंह तुलसी ने सर्जरी के जरिए जबड़े की टूटी हड्डियों को सही जगह पर लाकर स्थिर किया। इलाज और रिकवरी के बाद बच्चे के चेहरे की बनावट को दोबारा ठीक करने में मदद मिली और वह सामान्य जीवन में लौट आया। दूसरा मामला 35 वर्षीय सिद्धार्थ सिंह का था, जिन्हें दुर्घटना में चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। उनके चेहरे की कई हड्डियां छोटे–छोटे टुकड़ों में टूट गई थीं। कई अस्पतालों में इलाज कराने के बाद वह मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ पहुंचे। यहां डॉ. तुलसी और उनकी टीम ने सर्जरी के जरिए चेहरे की टूटी हड्डियों को सावधानीपूर्वक दोबारा सही जगह पर जोड़ा और मिनी टाइटेनियम प्लेटों की मदद से उन्हें स्थिर किया। क्षतिग्रस्त दांतों को भी बदला गया, जिससे दांतों के सही तरीके से मिलने में मदद मिली। इस उपचार से चेहरे की बनावट और उसकी कार्यक्षमता को दोबारा बेहतर बनाने में मदद मिली। इन मामलों पर बात करते हुए डॉ. सतिंदर पाल सिंह तुलसी ने कहा, "चेहरे की गंभीर चोटों, खासकर जब कई जगहों पर हड्डियां टूट जाती हैं, तो सर्जरी की सही योजना बनाना और हड्डियों को दोबारा सही स्थिति में लाना बहुत जरूरी होता है। इससे चेहरे की बनावट के साथ चबाने और जबड़े को हिलाने जैसी जरूरी क्रियाओं को भी ठीक करने में मदद मिलती है। बच्चों के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इलाज के दौरान चेहरे की हड्डियों के विकास और भविष्य में उनके सही तरीके से काम करने का ध्यान रखना पड़ता है। ये मामले बताते हैं कि गंभीर चोटों में समय पर इलाज और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के विशेषज्ञों का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। सही सर्जरी से चेहरे की बनावट और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, ताकि मरीज सामान्य जीवन में लौट सकें।" चेहरे पर गंभीर चोटों का इलाज कई चुनौतियों से जुड़ा होता है। ऐसी चोटें मरीज की शक्ल के साथ–साथ चबाने और जबड़े को हिलाने जैसी जरूरी क्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। खासकर जब चेहरे की कई हड्डियां टूट गई हों, तो उन्हें सही स्थिति में जोड़ने और स्थिर रखने के लिए समय पर इलाज और विशेषज्ञता जरूरी होती है। सिर और मस्तिष्क की चोटों के बारे में बात करते हुए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ के सीनियर डायरेक्टर, न्यूरोसर्जरी, डॉ. मनु रस्तोगी ने कहा, "सिर में चोट लगने पर उसकी गंभीरता का तुरंत पता नहीं चल पाता। सिर के अंदर खून बहना, मस्तिष्क में सूजन आना या रीढ़ से जुड़ी चोटों के कारण मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और तुरंत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। समय पर जांच और ऐसी सुविधा वाले अस्पताल में इलाज, जहां गंभीर चोटों के लिए सभी जरूरी विशेषज्ञ और संसाधन उपलब्ध हों, जटिलताओं को रोकने और मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ाने में मदद कर सकता है।" मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, लखनऊ में 24 घंटे इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। यहां इमरजेंसी के डॉक्टरों के साथ न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जन, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिलकर मरीजों का इलाज करते हैं। अस्पताल में आधुनिक जांच सुविधाएं, इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और हार्ट एंड न्यूरो कमांड सेंटर के तहत न्यूरो ट्रॉमा के मरीजों के लिए विशेष इंटेंसिव केयर सुविधा भी उपलब्ध है।

कपड़े की गोदाम में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र में नगर पालिका परिषद कार्यालय के पीछे स्थित एबीएम गारमेंट की गोदाम में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा–तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि गोदाम में रखे कपड़ों को काफी नुकसान होने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम के ऊपरी हिस्से से धुआं निकलता देख कर्मचारियों को आग लगने की जानकारी हुई। इसके बाद वहां काम कर रहे लोग बाहर निकल आए और दमकल विभाग को सूचना दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया और काफी प्रयास

के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। दमकल की तीन गाड़ियों की मदद से आग बुझा दी गई है। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और गोदाम में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, पड़ोसी दुकानदार रामकृष्ण पाल ने बताया कि वह केराकत स्थित अपने कार्यालय में थे, तभी घर से फोन पर आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि इस गली में पहले भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। रास्ते में अवरोध ा रहने से आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों के आवागमन में परेशानी हो सकती है। गोदाम में कपड़ों का काफी स्टॉक होने के कारण भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता आकलन के बाद ही चल सकेगा।

कारगर साबित हुई अखिलेश की रणनीति, एमएलसी चुनाव से बढ़ी सपा की ताकत

लखनऊ, (संवाददाता)। विधान परिषद चुनाव में सपा ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव और आगरा शिक्षक क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की। जबकि, इलाहबाद–झांसी स्नातक सीट से उसके प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव, वाराणसी स्नातक सीट से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ स्नातक सीट से उसकी प्रत्याशी कांति सिंह उल्लेखनीय रूप से आगे चल रही हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रणनीति इस चुनाव में कारगर साबित हुई। वर्ष 2020 में हुए विधान परिषद चुनाव में सपा को इन 11 सीटों में तीन सीटें मिली थीं। इस चुनाव में सपा न सिर्फ अपनी पुरानी तीनों सीटें बचाने में सफल होती दिख रही है, बल्कि दो और सीटें भी उसकी झोली में आना लगभग तय माना जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे समय मतगणना पर निगरानी रखी। आगरा में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल के साथ हुई मारपीट का वीडियो मंगलवार–बुधवार की दरम्यानी रात दो बजे एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। विधान परिषद चुनाव में सपा की दो सीटें जीतना और 5 पर बढ़त से सपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव में डॉ. संजयन त्रिपाठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी और साजिश के जरिए सपा प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाया। कहा कि इस मामले में भाजपा के नेताओं, उनके सहयोगियों और कथित तौर पर संलिप्त अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सबके सामने आ गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित युवक गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। मदेयगंज पुलिस ने करीब 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में वांछित 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीतापुर जिले के अटरिया थाना क्षेत्र के रनुवापारा निवासी अंकुश शुक्ला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ लखनऊ और सीतापुर के विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। उसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक, किशोरी के पिता ने 26 अक्टूबर को मदेयगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अंकुश शुक्ला ने घर में घुसकर किशोरी को डराया–धमकाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया ।

शराब के पैसे को लेकर विवाद में की थी दोस्त की हत्या

लखनऊ, (संवाददाता) ।कृष्णानगर थाना क्षेत्र में मजदूर सुखपाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी राजेश रावत उर्फ काली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों दोस्त थे और किराये के कमरे में साथ रहकर मजदूरी करते थे। शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था।पुलिस के मुताबिक, हरदोई जिले के टड़ियावां थाना क्षेत्र के कोटरा गांव निवासी जया देवी ने नौ अक्टूबर को कृष्णानगर थाने में अपने 27 वर्षीय बेटे सुखपाल की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर राजेश रावत उर्फ काली के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई थीं।

अब एक व्यक्ति खरीद सकेगा दो भूखंड, नैमिष और वरुण विहार योजना के लिए मची होड़

लखनऊ, (संवाददाता)। अब कोई भी व्यक्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के दो भूखंड खरीद सकेगा। अभी तक एक व्यक्ति को केवल एक भूखंड आवंटित करने का नियम था। एलडीए इस नियम में बदलाव करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव दो नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। नए नियम में ढील से उन खरीदारों को फायदा होगा जो एलडीए से दो भूखंड खरीदना चाहते हैं। वर्तमान में एक व्यक्ति, एक भूखंड के नियम के चलते लोग एलडीए की बजाय प्राधिकरण के आवंटी से रिसेल में दूसरा भूखंड खरीद लेते हैं। यदि बोर्ड की मंजूरी के बाद नियम बदला तो दो भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों को आवंटियों से रिसेल में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलडीए की इस समय दो आवासीय योजनाओं नैमिष और वरुण विहार में पंजीकरण हुआ है। आईटी सिटी और वेलनेस सिटी में भी पंजीकरण शुरू होना है। बोर्ड की मंजूरी के बाद लोग किसी एक योजना या अलग–अलग योजना में दो भूखंड खरीद सकेंगे। पहले दो भूखंड रखने पर लोगों को एक भूखंड सरेंडर करना पड़ा था। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में एलडीए में एक नेता ने अपना भूखंड सरेंडर किया था। साल 2001 में उन्हें और उनकी पत्नी को लॉटरी से भूखंड आवंटित हुए थे। एक विरोधी की शिकायत के बाद नेताजी उपभोक्ता फोरम तक गए पर उन्हें राहत नहीं मिली। इसी तरह आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना में भी एक नेता ने भूखंड सरेंडर किया था। अब प्रस्ताव पास होने के बाद सीधे दो भूखंड लेने वालों को कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए में अब तक नियम है कि कोई व्यक्ति एक भूखंड और स्ववित्त पोषित योजना का एक फ्लैट ले सकता था। इसी तरह वह प्रदेश में विकास प्राधिकरण और आवास विकास के दो भूखंड ले सकता था। एलडीए ने लोगों को राहत देने के लिए अब दो भूखंड देने का प्रस्ताव बनाया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर सहित कई योजनाओं में प्राधिकरण की कुछ दुकानें हैं।

छात्रों को पढ़ाई के लिए खून बेचने की नौबत भाजपा सरकार पर कलंक - राजेंद्र पाल गौतम

लखनऊ, (संवाददाता)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रयागराज में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए खून बेचने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालना पड़ रहा है। यह स्थिति प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और जरूरतमंद छात्रों को मिलने वाली सहायता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।राजेंद्र पाल गौतम मंगलवार को जौनपुर के मड़ियाहूं में कांग्रेस के 'छात्रों के हक की बात, युवाओं के साथ' कार्यक्रम के तहत युवाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि लाखों करोड़ रुपये के बजट वाले उत्तर प्रदेश में भी गरीब परिवारों के विद्यार्थी कोचिंग, किराये और भोजन का खर्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज की घटना को लेकर योगी

चक्रवाती तूफान से पशुओं को बचाने के लिए सतर्क रहें पशुपालक – सीवीओ

अयोध्या।चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के संभावित प्रभाव को देखते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. इंद्रदेव ने जिले के पशुपालकों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। पशुओं को पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे बांधने से बचें। उन्हें मजबूत छप्पर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखें, ताकि तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और भारी बारिश के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि न हो।उन्होंने पशुपालकों को सलाह दी कि बारिश के दौरान पशुओं को खुले स्थानों पर न छोड़ें और उनके चारे–पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को जलभराव वाले स्थानों पर बांधने से बचें तथा उनके रहने के स्थान पर पानी जमा न होने दें। तेज हवा के दौरान कमजोर छप्पर और असुरक्षित ढांचों के नीचे पशुओं को रखने से बचें।इसके अलावा पशुओं को बिजली के तारों और जलभराव वाले विद्युत उपकरणों से दूर रखें। किसी पशु के बीमार होने या घायल होने पर तत्काल पशु चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि मौसम सामान्य होने तक विशेष सतर्कता बरतें और पशुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

आरपीएफ अयोध्या कैंट ने आपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत मुंबई जा रहे सात नाबालिग बच्चों को बचाया

अयोध्या।आरपीएफ अयोध्या कैंट ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से सात नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया।सभी बच्चे मुंबई में खेतों में साग–सब्जी का काम करने जा रहे थे।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हरीश शाही ने बताया कि एएसआई रमेश कुमार यादव और कांस्टेबल अमित कुमार स्टेशन पर चेकिंग व गश्त कर रहे थे।इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 7 नाबालिग लड़के लावारिस हालत में मिले।पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे मुंबई में खेतों में काम करने जा रहे हैं।उन्हें एक व्यक्ति स्टेशन पर छोड़कर चला गया था,लेकिन वे उसका नाम–पता नहीं जानते थे।बताया कि बच्चों की उम्र और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें आरपीएफ थाने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) अयोध्या और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सूचना दी गई।इस संबंध मे एएचटीयू प्रभारी महेंद्र कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपरवाइजर घनश्याम यादव और केस वर्कर सुनीता यादव की मौजूदगी में बच्चों से पूछताछ की गई।पूछताछ में बच्चों को मुंबई में खेतों में काम करने के बदले प्रतिमाह 10 हजार रुपये वेतन देने की बात कही गई थी।बच्चों के माता–पिता भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वे अपनी सहमति से बच्चों को काम के लिए भेज रहे थे। इसके बाद सातों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।समिति ने आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभिभावकों को बच्चों से श्रम न कराने और उन्हें शिक्षा दिलाने की हिदायत देते हुए उनके सुपुर्द कर दिया।

रेलवे ट्रैक पर रखा लकड़ी का तख्त से लखनऊ–छपरा एक्सप्रेस से टकराया

अयोध्या।बड़ागांव रेलवे स्टेशन के पास देर रात रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का तख्त रखे जाने से हड़कंप मच गया। लखनऊ से चलकर छपरा जाने वाली ट्रेन संख्या 15054 लखनऊ–छपरा एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे तख्त से टकरा गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया।घटना के बाद ट्रेन करीब 13 मिनट तक खड़ी रही।बताते चले कि घटना बड़ागांव रेलवे स्टेशन से पूरब हरिदास के पुरवा के सामने की है। इस घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी तथा आफ सुरक्षा कर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए।इस संबंध में कैंट रेलवे स्टेशन प्रभारी निरीक्षक हरीश शाही और जीआरपी कैंट के थानाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने संयुक्त रूप से बताया कि रेलवे ट्रैक पर तख्त रखा जाना गंभीर मामला है।घटना में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।इन दोनों अधिकारियों ने बताया रेलवे ट्रैक पर तख्त किसने और किन परिस्थितियों में रखा।इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे की मंशा और हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका के संबंध में जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

अयोध्या जिला जेल से फरार कैदी शेरू को नौ माह बाद यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से किया गिरफ्तार,दूसरा अभी भी फरार

अयोध्या।जिला जेल अयोध्या से फरार कैदी शेरू को यूपी एसटीएफ ने नौ माह बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। ट्रांजिट रिमांड पर अयोध्या लाए जाने के बाद उसे जिला जेल में दाखिल करा दिया गया है।वहीं,उसके साथ फरार हुए दूसरे कैदी गोलू अग्रहरि की तलाश जारी है।मिली जानकारी के अनुसार,नौ माह पूर्व 28 जनवरी 2026 को शेरू और गोलू अग्रहरि जिला जेल से फरार हो गए थे। शेरू सुल्तानपुर जिले का निवासी है और हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद था।दोनों कैदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था।

मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते जेल अधीक्षक समेत 11 जेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था।करीब नौ माह बाद शेरू की गिरफ्तारी को फरार कैदियों की तलाश में जुटी एजेंसियों के लिए अहम सफलता माना जा रहा है।हालांकि, दूसरा कैदी गोलू अग्रहरि अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

कचहरी परिसर में चला सफाई अभियान,महापुरुषों की प्रतिमाओं की हुई धुलाई

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।दीपोत्सव के पूर्व स्वच्छता अभियान के तहत गुरुवार को अयोध्या कचहरी परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने परिसर की सफाई करने के साथ बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर समेत स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों की प्रतिमाओं की धुलाई की।सुबह करीब आठ बजे कचहरी परिसर पहुंचे महापौर ने नगर आयुक्त और नगर निगम की टीम के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उन्होंने परिसर का भ्रमण कर सफाई कार्यों का जायजा भी लिया।अभियान के दौरान चूने का छिड़काव करने के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा की धुलाई की गई। इसके बाद महापौर और नगर आयुक्त स्वतंत्रता सेनानी भवन पहुंचे। यहां आचार्य नरेंद्र देव, रमानाथ मेहरोत्रा और डॉ. राममनोहर लोहिया की प्रतिमाओं की सफाई की गई। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मृति पट्टिका को भी साफ किया गया। परिसर में स्थित जल प्याऊ के आसपास उगे खरपतवार को हटाया गया।महापौर ने परिसर के शौचालयों की स्वच्छता का भी निरीक्षण किया। कैंटीन के पीछे यूरिनल बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि परिसर में साफ–सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।अभियान में पार्षद सुशील मिश्र बबलू, पार्षद अनीता द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, जोनल अधिकारी सुभाष त्रिपाठी, चिंतन संस्था के आलोक सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सोनकर, सतीश पांडेय, चंद्रशेखर तिवारी, अवनीश मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रप्रीत सिंह बेदी, रुचिरा सिंह, आशीष कौर और मीना यादव मौजूद रहे।

भारतीय रेडक्रास सोसाइटी अयोध्या की नवनिर्वाचित जिला प्रबंध कार्यकारिणी को दिलाई गई शपथ

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।जिलाधिकारी अयोध्या शशांक त्रिपाठी ने कैंप कार्यालय सभागार में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, अयोध्या की नवनिर्वाचित जिला प्रबंधन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को रेडक्रास के मूल सिद्धांतों के अनुपालन की शपथ दिलाई।उल्लेखनीय है कि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, अयोध्या की जिला प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव दिनांक 21 सितंबर 2026 को संपन्न हुआ था।चुनाव में डॉ. अजय मोहन श्रीवास्तव सभापति,मिश्रीलाल उपसभापति तथा डॉ. सद्दाम खान को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।इसके अतिरिक्त डॉ. संदीप कुमार शुक्ला, डॉ. मिर्जा शाहाब शाह,रामानुज तिवारी, डॉ. मदन बरनवाल, डॉ. रविन्द्र शुक्ला, डॉ. विकास श्रीवास्तव, डॉ. अमित वर्मा, डॉ. विनय प्रकाश मौर्य,बसंतराम,मनोज कुमार वर्मा,शीतला प्रसाद गुप्ता, रीतेश कुमार,शक्तिराज श्रीवास्तव,जयशंकर त्रिपाठी, डॉ. अजय कुमार मिश्रा,देवेंद्रनाथ मिश्रा,पवन कुमार शर्मा, घनश्याम यादव तथा डॉ. कनक बिहारी पाठक सहित 19 कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की।इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को रेडक्रास के मूल सिद्धांतों कृमानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकताकृके प्रति निष्ठावान रहते हुए कार्य करने की शपथ दिलाई।कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या डॉ. देवेंद्र कुमार भट्टोरिया ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि सभी पदाधिकारी एवं सदस्य जनपद में रेडक्रास के उद्देश्यों के अनुरूप जनसेवा, मानवीय सहायता तथा जरूरतमंदों के कल्याण के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ करेंगे। इस अवसर पर डॉ. संदीप कुमार शुक्ला, जिला क्षय रोग अधिकारी अयोध्या एवं भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के प्रशासनिक सचिव ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम के दौरान राम सेवक,रामानुज,विवेक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वेतन न मिलने पर जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर,परिसर में लगा कूड़े का अंबार

अयोध्या।जिला अस्पताल में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए।हडताल पर गये कर्मचारियों ने इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना देकर नारेबाजी की।हड़ताल के चलते अस्पताल परिसर में जगह–जगह कूड़े का अंबार लग गया है,जिससे साफ–सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सितंबर से वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि पिछले आठ से नौ महीने से उनके पीएफ (भविष्य निधि) की कटौती भी नहीं की गई है।कर्मचारियों के मुताबिक,उन्हें महज 7,200 रुपये मासिक वेतन मिलता है,जिसमें से भी कटौती की जाती है।कर्मचारियों ने वेतन भुगतान को लेकर सुपरवाइजर तिवारी पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है।हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उनका बकाया वेतन तत्काल जारी किया जाए और भविष्य में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें बकाया वेतन नहीं मिल जाता,तब तक वे सफाई कार्य शुरू नहीं करेंगे।फिलहाल वेतन भुगतान का विवाद अब अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर असर डालने लगा है। ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों को गंदगी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने वाले आरक्षी सर्वेश यादव बने मुख्य आरक्षी

अयोध्या।उत्तर प्रदेश पुलिस के बास्केटबॉल खिलाड़ी आरक्षी सर्वेश कुमार यादव को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्य आरक्षी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।उनकी इस उपलब्धि से पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है।बताते चले कि जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता के पुरुष बास्केटबॉल फाइनल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने केरल पुलिस को 69–42 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था।23 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 27 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की थी।इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के शानदार प्रदर्शन और खेल उपलब्धि के प्रोत्साहन स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद अयोध्या में तैनात आरक्षी सर्वेश कुमार यादव को मुख्य आरक्षी पद पर पदोन्नति प्रदान की है।सर्वेश कुमार यादव की यह उपलब्धि पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत है।इस मौके पर इन्हें सम्मानित करते हुए एसपी ग्रामीण राधेश्याम राय ने कहा इससे पुलिस बल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।

'न्याय पंचायत नेहरूनगर में बालक्रीड़ा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन'

जौनपुर । शासन के आदेशानुसार जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सिरकोनी के खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार सिंह द्वारा माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और उनके सम्मुख धूप दीप प्रज्ज्वलित करके न्याय पंचायत नेहरूनगर के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की बालक्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारम्भ दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को नोडल शिक्षक संकुल डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय नेहरूनगर के परिसर में किया गया। माँ सरस्वती जी के पूजनोपरान्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक भगेलूराम , नोडल शिक्षक संकुल डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव तथा उपस्थित अन्य सभी शैक्षणिक स्टाफ द्वारा खण्ड शिक्षा का माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ प्रदान करके स्वागत किया गया। प्रतियोगिता स्थल पर फीता काटकर बालक्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार सिंह द्वारा उपस्थित बच्चों, शैक्षणिक स्टाफ तथा अभिभावकों को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि शिक्षा के साथ– साथ बच्चों का स्वास्थ्य और शारीरिक मानसिक विकास भी आवश्यक होता है। पठन –पाठन के साथ– साथ खेलकूद भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान शिक्षा नीति में भी बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलकूद, मनोरंजन और गतिविधियों के साथ शिक्षा की ओर अग्रसर करने की बात कही गई है। हमें यह कहने में अत्यधिक गर्व का अनुभव हो रहा है कि शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ– साथ विभिन्न प्रकार के खेलकूद के संसाधन भी उपलब्ध कराये गये हैं जिनसे बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों से पढ़कर निकले बच्चे भी शहरों में स्थित कान्वेंट स्कूलों के बच्चों की भांति विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं और क्रीड़ा स्पर्धाओं में अच्छे मानक और मानदण्ड स्थापित कर रहे हैं। निश्चित ही परिषदीय विद्यालयों के हमारे यह बच्चे अपनी प्रतिभा लगन और मेहनत के दम पर अपने शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग करके न्याय पंचायत, ब्लाक और जनपद के साथ– साथ प्रदेश को भी निपुण प्रदेश बनायेंगे। मैं प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले तथा अन्य सहयोगी सभी बच्चों ,उनके अभिभावकों तथा समस्त शैक्षणिक स्टाफ को यह प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संचालित करने की शुभकामनाएं देता हूँ। आज की इस प्रतियोगिता में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर में बालक तथा बालिका वर्ग के अलग– अलग क्रमशः दौड़, ऊंची कूद, लम्बी कूद, शाटपुट–गोलाफेंक, डिस्कस थ्रो, कबड्डी , खो–खो, शतरंज, आदि विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को सुचारू रुप से सम्पन्न कराने में उच्च प्राथमिक विद्यालय नेहरूनगर के खेल अनुदेशक विजय प्रकाश पाल, प्राथमिक विद्यालय मसऊदपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक आनन्द कुमार निषाद, प्राथमिक विद्यालय नाहरपुर के शिक्षक राजबहादुर यादव, उच्च प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर बहरीपुर के शिक्षक अरविन्द कुमार यादव, कम्पोजिट विद्यालय शिवपुर के शिक्षामित्र अरविन्द कुमार सिंह, प्राथमिक विद्यालय हूसेपूर के शिक्षामित्र आनन्द कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय गयासपुर के शिक्षक व संकुल कुलदीप का विशेष योगदान रहा। प्रधानाध्यापक गजेन्द्र सिंह व शिक्षिका यादव मीरा, प्राथमिक विद्यालय कबूलपुर प्रथम की प्रधानाध्यापक वन्दना सिंह तथा शिक्षक योगेश श्रीवास्तव, प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापक शालिनी सिंह, प्राथमिक विद्यालय केशवपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापक शिवांकी सिंह तथा शिक्षक सौरभ कुमार, प्राथमिक विद्यालय कबूलपुर द्वितीय की शिक्षिका अन्जू सिंह का विशेष योगदान रहा । आज की इस प्रतियोगिता में तथा विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों के भोजन ,जलपान और बैठक की सम्पूर्ण व्यवस्था मेजबान विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेहरूनगर के प्रभारी प्रधानाध्यापक भगेलूराम तथा प्राथमिक विद्यालय नाहरपुर के प्रधानाध्यापक व पूर्व एन पी आर सी राजकुमार यादव का विशेष योगदान रहा जिन्होंने एक– एक बच्चे को बैठाकर अत्यंत आत्मीयता और भोजन मंत्र के साथ भोजन करवाया। उच्च प्राथमिक विद्यालय नेहरूनगर के वरिष्ठ शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, शिक्षिका डॉ. प्रतिमा सिंह,अनुदेशक मोहम्मद शाकिब ने पूरे खेल परिसर में बच्चों को अपना स्नेह प्रदान करते हुए अनुशासन की डोर में बांधे रखा। आप सभी के प्रयास से सभी बच्चे अनुशासित रहते हुए खेल समाप्ति और मेडल वितरण तक उत्साहपूर्वक मैदान में डटे रहे। अंत में नोडल शिक्षक संकुल डॉ.आशीष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्रीड़ा स्थल पर उपस्थित सभी महिला– पुरुष शैक्षणिक स्टाफ का क्रमशः सहयोग लेते हुए उनके द्वारा विजेता बच्चों और विजयी टीम को मेडल पहनवाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा आगे की प्रतियोगिताओं में सफल होने का आशीर्वाद दिया गया।। नोडल शिक्षक संकुल डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज की इस बालक्रीड़ा प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु उपस्थित सभी शैक्षणिक स्टाफ, बच्चों तथा उनके अभिभावकों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। मिष्ठान वितरण और राष्ट्रगान व जयघोष के पश्चात आज की इस बालक्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन किया गया।

छह किमी के दायरे में 45 हजार की आबादी में दहशत, फुटप्रिंट खोजे जा रहे

वाराणसी, (संवाददाता)। छावनी (कैंटोमेंट) क्षेत्र में पिछले छह दिनों से तेंदुए की मौजूदगी की खबरों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। करीब छह किलोमीटर के दायरे में करीब 45 हजार की आबादी दहशत है। छावनी समेत नदेसर, राजा बाजार, वरुणा ब्रिज, भोजूबीर समेत 10 क्षेत्रों के लोगों में तेंदुए को लेकर खौफ है। कैंटोमेंट क्षेत्र शहर का अति–संवेदनशील और प्रमुख इलाका माना जाता है, जहां डीएम, पुलिस कमिश्नर सहित कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के आवास हैं। साथ ही, इसी क्षेत्र में कई स्टार–रेटेड होटल हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों विदेशी और घरेलू पर्यटकों का आवागमन रहता है। तेंदुए के खौफ का सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा है। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल, जहां बीते बृहस्पतिवार को तेंदुआ दिखा था, उसे एहतियातन बंद कर कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर चलाई जा रही हैं। यहां तक कि शिक्षकों को भी स्कूल में जाने से मना किया गया है। वन विभाग ने वन्यजीव की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। इलाके में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और ट्रैप कैमरों के माध्यम से चप्पे–चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अब तक तेंदुए की सीधी मौजूदगी का कोई पुख्ता प्रमाण या फुटेज हाथ नहीं लगा है। सोमवार देर रात तक टेक्निकल ग्राउंड के आसपास वन्यजीव दिखाई देने की चर्चाओं से हड़कंप मचा रहा, लेकिन मौके पर पहुंचे बचाव दल को किसी जानवर की मौजूदगी की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। इससे पहले 39 जीटीसी सैन्य परिसर में भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया था। डीएफओ के अनुसार, कैमरों और जमीन पर की गई छानबीन में केवल कुत्तों के पंजों के निशान पाए गए हैं। इसके बावजूद विभाग ने सुरक्षा के तौर पर परिसर में पिंजरा लगाया है और अगले 10 दिनों तक लगातार निगरानी रखने का निर्णय लिया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।